पूर्ण बेंच

माननीयन्यायमूर्ति मेहर सिंह, सीजे पीसी पंडित और आरएस नरुला, के समक्ष

चानन दास,—*अपीलकर्ता बनाम*

भारत संघ और अन्य, - *उत्तरदाता।*

1964 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 305

8 मई, 1968

उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड V, अध्याय 3-B, *नियम* 1, *परंतुक- एकल फज द्वारा किसी मामले को डिवीजन बेंच को निर्णय देने के लिए संदर्भित करनाकेवल कानून का सवाल है और मामले को वापस भेजने का सवाल है। एकल न्यायाधीश[1] मामले में अंतिम रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है- ऐसे निर्णय के खिलाफ दायर पत्र पेटेंट अपील- पत्र पेटेंट पीठ- क्या पूर्व डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच की जा सकती है।*

बहुमत से आयोजित किया गया (मेहर सिंह, सी.जे. और नरुला, जे., पंडित, जे. *(ख)* - यदि कोई विद्वान एकल न्यायाधीश किसी मामले को खंडपीठ को भेजता है और उक्त खंडपीठ केवल कानून के प्रश्न पर निर्णय लेती है और फिर मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज देती है, तो विद्वान एकल द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील में लेटर्स पेटेंट बेंच, न्यायाधीश कानून के उपरोक्त प्रश्न पर पहले के निर्णय (पीठ) के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच नहीं कर सकता है। एक खंडपीठ द्वारा कानून के अंतर-पक्षकारों के प्रश्न पर निर्णय, जो किसी अन्य खंडपीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए खुला नहीं है, भले ही ऐसी पीठ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से अपील की सुनवाई कर रही हो। यदि यह अन्यथा था, तो इसका मतलब यह होगा कि इस तरह के लेटर्स पेटेंट अपील में एक डिवीजन बेंच पहले की डिवीजन बेंच के फैसले पर पुनर्विचार करने में सक्षम हो सकती है, जो नहीं हो सकता है, या यह पिछली डिवीजन बेंच द्वारा तय किए गए मामले को एक बड़ी बेंच के पुनर्विचार के लिए भेजने पर विचार कर सकता है, जो इस तरह के निर्णय के निर्णायक और बाध्यकारी चरित्र को खत्म कर देगा।

[पैरा 7 और 26],

(पंडित, *जे. कॉन्ट्रा द्वारा)* कहा गया है कि यदि जिस खंडपीठ को मामला भेजा जाता है, वह कानून के अमूर्त प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद, इसे मामले के तथ्यों पर लागू करती है और इसमें उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज देती है, तो डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया कानून का बिंदु अंतिम और *अंतर-पक्षकार* बन जाता है। डिवीजन बेंच का निर्णय बाद के चरणों में *न्यायाधीन* के रूप में कार्य करेगा और इसमें उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर मामले का निर्णय करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम निर्णय से पेटेंट अपील पत्र में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते *कि लेटर्स* पेटेंट अपील में उचित स्तर पर निर्णय लिया जाए। यदि, हालांकि, अपने द्वारा तय किए गए कानून के सिद्धांत को लागू किए बिना, डिवीजन बेंच मामले को अंतिम निर्णय के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजती है, तो डिवीजन बेंच का आदेश न्यायिक रूप से काम नहीं करेगा, *न कि अंतिम रूप से* अंतर-पक्षकारों *के रूप में तय किया गया है*। उस मामले में, *अंतर-पक्षकारों* का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश का होगा और उनके फैसले से लेटर्स पेटेंट अपील में, अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह पहले की डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता को चुनौती दे सके।

[पैरा 22],

- ^ *एक* [द्विस पीठ] *जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति ^ ए^ सीआर बहादुर और माननीय न्यायमूर्ति पी सी पंडित शामिल हैं, एक बड़ी पीठ को*

- ^ एच 2 एल « ^ *होमे सीएच^ जून का। श्री एम^हर एसएम ई आर जस्टिस पीसी पंडित और माननीय न्यायमूर्ति आर एस नरुला*

उनके द्वारा भेजे गए कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद दिनांक 07 मई, 1968 को निर्णय के लिए खंडपीठ को आसानी से लौटा दिया गया।

माननीय न्यायमूर्ति एच आर खन्ना के दिनांक 24 मार्च, 1964 के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील। 1961 का 1492 ।

राम रंग और एस.के. पिपट, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

वी.पी. काकरिया और आर.एस. अमोल, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

मेहर सिंह, सीजे- इस मामले में विवाद कमल जिले के पानीपत में वार्ड नंबर 7 में आर -765 वाली विस्थापित संपत्ति को 769 में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जिसकी कीमत पुनर्वास अधिकारियों द्वारा 733 रुपये आंकी गई है। संपत्ति के दो दावेदार हैं, गोधा राम प्रतिवादी 3, और चानन दास अपीलकर्ता, दोनों विस्थापित व्यक्ति हैं। 1 जून, 1961 के अपने आदेश में, जिसके साथ केंद्र सरकार ने विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 44) की धारा 33 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार के 27 सितंबर, 1961 के पत्र के अवर सचिव, मुख्य निपटान आयुक्त से प्रतीत होता है। अधिनियम की धारा 24 के तहत संशोधन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 30 के रूप में संदर्भित '1955 नियम' के रूप में 24 मार्च, 1961 को इस आशय से संशोधन किया गया था कि दो विस्थापित व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में संपत्ति उसी को दी जाएगी जिसके पास सबसे अधिक मुआवजा है। इसलिए संपत्ति गोधा राम प्रतिवादी 3 को हस्तांतरित की जाए क्योंकि उसका 5,749 रुपये का मुआवजा अपीलकर्ता की तुलना में अधिक था, जिसके मुआवजे की राशि 4,279 रुपये थी। 24 मार्च, 1961 को संशोधन होने से पहले 1955 के नियमों के नियम 30 में यह प्रावधान किया गया था कि संपत्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसका सकल मुआवजा संपत्ति के मूल्य के सबसे करीब था, और जब नियम उस रूप में था, तो जाहिर है, संपत्ति अपीलकर्ता को दी जानी थी क्योंकि उसका मुआवजा संपत्ति के मूल्य के सबसे करीब था। जब तक मुख्य बंदोबस्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की सुनवाई की गई, लेकिन इस मामले में अपील के चरण के बाद, ऊपर बताए गए नियम में संशोधन किया गया था। इसलिए, मुख्य निपटान आयुक्त की राय थी कि संशोधित नियम प्रतिस्पर्धी दावेदारों, अपीलकर्ता पर लागू होता है।

और गोधा राम प्रतिवादी 3. इसलिए उन्होंने गोधा राम प्रतिवादी के पक्ष में फैसला किया।

(2) थेज अपीलकर्ता ^1 नवंबर, 1961, ने मुख्य निपटान आयुक्त के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए 1961 की 1 सिविल रिट 1 संख्या दायर की और इसे रद्द करने के लिए रिट, निर्देश या आदेश की मांग की। इस याचिका की सुनवाई के दौरान एक प्रश्न उठा कि क्या नियम 30 का संशोधन पूर्वव्यापी था ताकि इसके लागू होने की तारीख पर पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाही पर लागू किया जा सके, याचिका की सुनवाई कर रहे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 31 अक्टूबर, 1963 को एक बड़ी पीठ को प्रश्न का संदर्भ दिया। उस पर अपीलकर्ता की 1961 की याचिका संख्या 1492, इसी तरह की कई अन्य याचिकाओं के साथ, और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील, मेला राम वी। *भारत सरकार* (1) की सुनवाई दुआ और खन्ना, जेजे की खंडपीठ द्वारा की गई थी, जिन्होंने 19 फरवरी, 1964 को अपना फैसला सुनाया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने कहा था कि संशोधित नियम 30 पूर्वव्यापी रूप से लागू था, जो संशोधन की तारीख पर मुख्य निपटान आयुक्त के समक्ष लंबित अधिनियम की धारा 24 के तहत संशोधन आवेदनों पर लागू होता है। शुरुआत में फैसले का शीर्षक 1963 के एलपीए नंबर 92, मेला राम बनाम मेला राम से शुरू होता है। *भारत सरकार* (1), लेकिन फैसले की पहली कुछ पंक्तियों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्य याचिकाओं और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के साथ, अपीलकर्ता की याचिका, यानी 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 पर भी इस प्रश्न पर पीठ द्वारा सुनवाई की गई थी। प्रश्न पर अपना निर्णय देने के बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने निर्देश दिया कि "सभी रिट याचिकाओं को अब एकल पीठ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए"। अपीलकर्ता की 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया गया आदेश था- "आदेश के लिए 1963 का एलपीए नंबर 92 देखें। इसलिए यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीशों का वह निर्णय अपीलकर्ता की इस याचिका में भी दिया गया था। उसके बाद अपीलकर्ता की यह याचिका खन्ना, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आई और विद्वान न्यायाधीश ने 24 मार्च, 1964 को इसमें यह आदेश दिया- " मेला राम बनाम *मेला राम* मामले *में खंडपीठ के फैसले को देखते हुए। भारत सरकार* (1), यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं". इसलिए अपीलकर्ता की याचिका 24 मार्च, 1964 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी। एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने 1964 के लेटर्स पेटेंट, एलपीए नंबर 305 के खंड 10 के तहत चानन *दास* बनाम *भारत संघ,* जिसमें गोधा राम प्रतिवादी 3 है, दायर किया।

(1) 1963 के एलपीए संख्या 92 पर 19 फरवरी, 1964 को निर्णय लिया गया।

(3) 1964 का यह एलपीए नंबर 305, *चानन दास* वी। *यूनियन ओजे इंडिया,* महाजन, जे और मेरे समक्ष सुनवाई के लिए आया और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अन्य अपील जीवन *दास* बनाम *भारत के समक्ष दायर की गई। भारत संघ,* 1966 का एलपीए नंबर 1। हमने पाया कि 24 मार्च, 1961 से नियम 30 के संशोधन के प्रभाव के संबंध में उन अपीलों में उठाए गए प्रश्न पर, इस न्यायालय में दो ♦ खंडपीठों के निर्णयों का टकराव था, अर्थात् *मेला राम* बनाम मेला राम। *भारत सरकार* (1), और *हरहंस लाई वी। भारत संघ* (2) उन मामलों में परस्पर विरोधी खंडपीठ के निर्णयों के विचार से, हमने इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया-

> क्या 24 मार्च, 1961 को संशोधित नियम 30 उस तारीख को लंबित या उसके बाद विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम की धारा 24 और 33 के तहत दायर संशोधनों पर लागू होता है?

इस संदर्भ की सुनवाई दुआ और महाजन, जेजे और मेरे तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की। इस सवाल का जवाब देने वाला हमारा फैसला 26 सितंबर, 1966 को सुनाया गया था। महाजन, जे. और मेरी राय थी कि 24 मार्च, 1961 को संशोधित नियम 30 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया गया था, ताकि 24 मार्च, 1961 को अधिनियम की धारा 24 और 33 के तहत लंबित संशोधन आवेदनों ♦ को प्रभावित किया जा सके, लेकिन दुआ, जे, मेजा *राम के मामले* में अपने विचार का पालन किया। इसलिए बहुमत की राय से जवाब दिया गया कि संशोधित नियम 30 24 मार्च, 1961 को लंबित संशोधनों पर लागू नहीं होता है।

)

(4) उसके बाद अपीलकर्ता की अपील, 1964 की एलपीए संख्या 305, शमशेर बहादुर आर डी पंडित, जेजे के समक्ष सुनवाई के लिए आई और विद्वान न्यायाधीशों ने 22 अगस्त, 1967 को इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया: –

> "यदि एक विद्वान एकल न्यायाधीश किसी मामले को डिवीजन बेंच को भेजता है और उक्त डिवीजन बेंच केवल कानून के प्रश्न पर फैसला करती है और फिर उस मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज सकती है, तो लेटर्स पेटेंट बेंच, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के खिलाफ एक आवेदन में, कानून के प्रश्न पर पूर्व की खंडपीठ के दृष्टिकोण की शुद्धता क्या है? यदि हां, तो इसके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है,

(2) 1959 के सीडब्ल्यू 513-डी का निर्णय 31 दिसंबर, 1963 को किया गया।

यदि उसे खंडपीठ के फैसले पर संदेह है? क्या वह कानून के उस प्रश्न को पूर्ण पीठ के पास नहीं भेज सकती? या अगर इस बीच, किसी अन्य मामले में पूर्ण पीठ ने पहले ही कानून के सवाल पर पिछली खंडपीठ के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है, तो क्या उस फैसले को लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है?

यह वह प्रश्न है जो ऊपर वर्णित परिस्थितियों में विचार के लिए इस पीठ के समक्ष आया है।

(5) एक बात सबसे पहले स्पष्ट है कि मेला *राम* बनाम *कबभारत सरकार* (1) का निर्णय 19 फरवरी, 1964 को दुआ और खन्ना, जेजे की एक खंडपीठ द्वारा किया गया था, इसके साथ ही अपील पर अपीलकर्ता की 1961 की सिविल रिट याचिका संख्या 1492 पर भी सुनवाई की गई थी। बेशक, लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 के तहत ऐसी अन्य याचिकाएं और एक अन्य अपील भी थी जिन पर उसी समय सुनवाई हुई थी। दुआ और खन्ना, जेजे की खंडपीठ के फैसले में उन सभी मामलों को शामिल किया गया, जिसमें अपीलकर्ता की 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 भी शामिल थी। डिवीजन बेंच ने सभी मामलों में दलीलें सुनीं और एक फैसले द्वारा उसके समक्ष प्रश्न का निपटारा किया, जो निर्णय मेला राम बनाम *मेला राम* के *मामले में संलग्न था।भारत सरकार* (1), और, जहां तक अपीलकर्ता की सिविल रिट संख्या 1492 का संबंध है, 1961 का आदेश यह था कि, यह देखने के उद्देश्य से कि इसमें क्या आदेश दिया गया था, 1963 के एलपीए संख्या 92 में मुख्य निर्णय का संदर्भ दिया जाए। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता की 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 में जवाब लौटाया कि संशोधित नियम 30 24 मार्च, 1961 को लागू होने की तारीख पर प्रभावी रूप से लागू था, अर्थात यह अधिनियम की धारा 24 के तहत उस तारीख को लंबित संशोधन आवेदनों पर लागू था। इस प्रकार यह 1961 के सिविल रिट नंबर 1492 में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता और गोधा राम प्रतिवादी 3 के बीच एक निर्णय था।

(6) जब, खन्ना, जे. ने 24 मार्च, 1961 को संशोधित नियम 30 के ऑपरेटिव प्रभाव पर इस मामले में किए गए डिवीजन बेंच के पहले के फैसले के बाद 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 को खारिज कर दिया था, तो अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की और उस अपील पर महाजन ने सुनवाई की। जे और मैं, उस समय नियम 30 की व्याख्या के इस पहलू पर डिवीजन बेंच का निर्णय था, जैसा कि संशोधित किया गया था, जो पारस्परिक था और इस प्रकार उनके बीच निर्णायक था। इस मामले पर निर्णयों के टकराव के बावजूद,

21 जुलाई, 1966 के हमारे संदर्भ के आदेश में उल्लिखित, 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 में 19 फरवरी, 1964 को किया गया डिवीजन बेंच का निर्णय निर्णायक और बाध्यकारी था क्योंकि अपीलकर्ता और गोधा राम प्रतिवादी 3, उस याचिका के पक्षकार थे। ताकि यह मामला खन्ना, जे के 1961 के सिविल रिट नंबर 1492 को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील में हमारे सामने बहस के लिए खुला न हो। यह अभी भी हमारे लिए खुला मामला था कि हम जीवन दास बनाम जीवन दास की दूसरी अपील में एक बड़ी पीठ को संदर्भित करें । *भारत संघ*, 1966 का एलपीए नंबर 1। इस मामले पर उस समय हमारे समक्ष बहस नहीं हुई थी और इसलिए हमने संशोधित नियम 30 की व्याख्या के प्रश्न को संदर्भित किया क्योंकि यह जीवन दास बनाम अन्य अपील में भी उठा था। *भारत संघ*, 1966 का एलपीए नंबर 1। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि यदि यह मामला उस समय हमारे समक्ष विवाद का विषय होता तो हम अपीलकर्ता की अपील को बड़ी पीठ के पास नहीं भेज सकते थे क्योंकि हम 1961 की सिविल रिट संख्या 1492 में अपीलकर्ता द्वारा डिवीजन बेंच के फैसले में तय किए गए मामले का संदर्भ तीन न्यायाधीशों की पीठ को नहीं दे सकते थे। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस याचिका को खारिज करने से लेटर्स पेटेंट का खंड 10। इस पीठ के समक्ष अब जो प्रश्न है, वह इस मामले के इस पहलू पर मैंने अभी जो कुछ कहा है, उस पर कुछ संदेह पैदा करता है। इसलिए, यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि 19 फरवरी, 1964 को 1961 के सिविल रिट नंबर 1492 में डिवीजन बेंच के फैसले की कानून में वास्तव में क्या स्थिति है /

(7) Siny सत्यध्यान KGosal3 v.r देवराजिन>इदेबी *(3) में, त्रिददर्ों ने कुछ हद तक वर्तमान के समान मामलों* में न्याय के नियम को लागू करने *के* प्रश्न पर विचार किया , और उनके लॉर्डशिप ने कहा:

> पीठ ने कहा, '*न्यायिक* फैसलों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर पुनर्विचार का सिद्धांत आधारित है. इसमें यह कहा गया है कि एक बार *निर्णय लेने के बाद* इसे फिर से घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से यह पिछले मुकदमेबाजी और भविष्य के मुकदमेबाजी के बीच लागू होता है। जब कोई मामला - चाहे तथ्य के प्रश्न पर हो या कानून के प्रश्न पर - एक मुकदमे या कार्यवाही में दो पक्षों के बीच तय किया गया है और निर्णय अंतिम है, या तो क्योंकि उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई थी या क्योंकि अपील खारिज कर दी गई थी, या कोई अपील नहीं है, तो कोई भी पक्ष नहीं होगा।

(3) ए.जे.आर. 1960 एस.सी. 941.

> भविष्य में मामले को फिर से उठाने के लिए एक ही पक्ष के बीच मुकदमा या कार्यवाही की अनुमति दी गई। न्यायिक न्याय का यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में मुकदमों के संबंध में सन्निहित है; लेकिन जहां धारा 11 लागू नहीं होती है, वहां भी मुकदमेबाजी में अंतिम ता प्राप्त करने के उद्देश्य से अदालतों द्वारा न्याय का सिद्धांत लागू किया गया है। इसका परिणाम यह है कि मूल अदालत के साथ-साथ किसी भी उच्च न्यायालय को भविष्य में किसी भी मुकदमे में इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि पिछला निर्णय सही था।
>
> न्यायिक निर्णय का सिद्धांत एक ही मुकदमे में दो चरणों के बीच इस हद तक भी लागू होता है कि एक अदालत, चाहे ट्रायल कोर्ट हो या उच्च अदालत, जिसने पहले चरण में एक तरह से किसी मामले का फैसला किया हो, पार्टियों को उसी कार्यवाही के बाद के चरण में मामले को फिर से उत्तेजित करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि, क्या इसका मतलब यह है कि क्योंकि मुकदमे के पहले चरण में एक अदालत ने एक तरह से एक मध्यस्थ मामले का फैसला किया है और वहां से कोई अपील नहीं की गई है या कोई अपील नहीं की गई है, एक उच्च न्यायालय कर सकता है। उसी मुकदमे के बाद के चरण में इस मामले पर फिर से विचार नहीं करें?

और उनके लॉर्डशिप ने तब एक जवाब दिया कि ऐसे मामले में, उन मामलों को छोड़कर, जहां आदेश मामले का अंतिम निपटारा है, वार्ताकारी मामले में निर्णय *न्यायिक* रूप से काम नहीं करता है और अंतिम अपील योग्य निर्णय या डिक्री के खिलाफ अपील में पुनर्विचार के लिए खुला है। जाहिर है कि 24 मार्च, 1961 से संशोधन नियम 30 के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में कानून के सवाल पर 1961 के अपीलकर्ता की सिविल रिट संख्या 1492 में डिवीजन बेंच का निर्णय मध्यस्थ मामले या मध्यस्थ चरित्र का निर्णय नहीं था, बल्कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण सवाल और गुण-दोष पर निर्णय था। यह एक खंडपीठ द्वारा *पारस्परिक निर्णय* था, जिसमें से इस न्यायालय में अपील के लिए कोई जगह नहीं है, और इस पर केवल तभी पुनर्विचार किया जा सकता है जब इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की सिविल रिट संख्या 1492 के निपटान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की जाए। इसलिए, यह एक खंडपीठ द्वारा कानून के अंतर-पक्षकारों के प्रश्न पर निर्णय है, जो किसी अन्य खंडपीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए खुला नहीं है, भले ही ऐसी पीठ अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने वाले एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील की सुनवाई कर रही हो। यदि यह अन्यथा था, तो इसका मतलब यह होगा कि इस तरह के पत्र पेटेंट अपील में एक खंडपीठ हो सकती है

> पहले की खंडपीठ के निर्णय पर पुनर्विचार करने में सक्षम, जो नहीं हो सकता है, या यह पिछली खंडपीठ द्वारा तय किए गए मामले को एक बड़ी पीठ के पुनर्विचार के लिए भेजने पर विचार कर सकता है, जो इस तरह के निर्णय के निर्णायक और बाध्यकारी चरित्र को समाप्त कर देगा। निस्संदेह, जैसा कि मैंने कहा है, जब मामला उच्चतम न्यायालय में अपील में जाता है तो वहां न्याय का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन, जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, अपीलकर्ता की याचिका में खंडपीठ का निर्णय निर्णायक और पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है। यह स्पष्ट है कि 1964 के एलपीए संख्या 305 में पूर्ण पीठ का निर्णय, *चानन दास* बनाम चानन *दासभारत संघ,* और 1966 का एलपीए नंबर 1 *जीवन दास* बनाम *भारत संघ।भारत संघ, केवल बाद के मामले में प्रभावी है, अर्थात्,* जीवन दास *बनाम* भारत *के मामले में।भारत संघ, लेकिन अपीलकर्ता,* चानन दास *बनाम* भारत *की अपील के मामले में नहीं। भारत संघ।*इसी तरह का एक प्रश्न कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम स्पॉंगल्स एंड ग्लू मैन्युफैक्चरर्स और अन्य *(4) में विचार के लिए आया था,* जिसे ग्रोवर, जे और मैंने सुना था। उस मामले में पहले एक खंडपीठ द्वारा, अंतर-पक्षकारों के मामले में, यह माना गया था कि कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, 1949 का नियम 17 *अंतर्अधिकार* क्षेत्र में था, लेकिन एक अन्य मामले में एक पूर्ण पीठ ने बाद में कहा कि नियम 17 *अधिकार क्षेत्र से बाहर है।*यदि नियम 17 को *अधिकार क्षेत्र से बाहर* माना जाए तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दावे पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो यह समय से बाहर हो चुका है। एकल न्यायाधीश के निर्णय के बाद जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील की गई थी, तो यह आग्रह किया गया था कि हालांकि पहले इसी मामले में अंतर-पक्षकारों ने नियम 17 को *इंट्रा वाइल्स* माना था, जिसका परिणाम यह था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दावा विफल हो गया था, लेकिन उसके बाद एक पूर्ण पीठ ने उस नियम को *अधिकार से परे* माना था, इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दावे को समय से बाहर बताकर खारिज नहीं किया जा सकता था। इस आपत्ति पर यह निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए

यह तर्क उपलब्ध नहीं था, क्योंकि विचाराधीन नियम की वैधता पर डिवीजन बेंच के अंतर-पक्षकारों का पूर्व निर्णय पक्षकारों के बीच *न्यायाधिकार* था और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एम्लोवेस स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के खिलाफ एक एनेल बीवी में बाद में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर पुनर्विचार के लिए खुला नहीं था। फैसला बीवी ग्रोवर, जे. को दिया गया था, जिनके साथ मैंने सहमति व्यक्त की थी, और *सत्यध्यान घोषाल के मामले* और अन्य मामलों के बाद यह मामला आयोजित किया गया था।

(4) आई.एल.आर. *(1967) 2* पुन)। 694-1967 करी। कानून जॉन। (Pb. and Hry.), .329.

जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, डिवीजन बेंच का पिछला निर्णय *न्यायाधीन* था और एक अन्य मामले में बाद में पूर्ण पीठ के फैसले के बावजूद उस मामले में अपीलकर्ता द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में इसके पुनर्विचार पर रोक लगा दी गई थी, जो डिवीजन बेंच के फैसले के विपरीत था और अपीलकर्ता के दावे का समर्थन करता था। इस दृष्टिकोण के समर्थन में विचार किए गए अन्य मामले बालकिशन *दास बनाम थे। परमेश्श्री दास* (5), जो इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय है, *लक्ष्मीनारायण* बनाम *सुल्तान जहां बेगम* (6) और *श्यामाचरण रघुबर प्रसाद* बनाम *श्योजी भाई जयराम छत्री* (7), तीनों मामलों में लिया गया दृष्टिकोण वही था जो हमने कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम *कर्मचारी राज्य बीमा निगम* में *लिया था। स्पैंगल्स और गोंद निर्माता* (4). हैदराबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय *पिचू अय्यंगर* बनाम *हैदराबाद से सहमत नहीं थे। रामानुज* (8), बाक्यूज इसे सत्यध्यान घोषाल के मामले *में उनके लॉर्डशिप के फैसले के विपरीत माना गया था।* विशेष रूप से दो तर्क, जो उस मामले में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए थे, पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला यह था कि चूंकि एक अपील पुन: सुनवाई की प्रकृति में है, इसलिए अपील में दी जाने वाली राहत को ढालने में अपीलीय न्यायालय को उन तथ्यों और घटनाओं को भी ध्यान में रखने का अधिकार था जो डिक्री के बाद अस्तित्व में आए थे, जैसे कि अपील में निर्णय दिए जाने के बाद विधायी परिवर्तन और इसकी शक्तियां केवल यह देखने तक सीमित नहीं थीं कि क्या अपील के खिलाफ अपील की गई निर्णय सही है। कानून उस समय जैसा था जब इसे दिया गया था। यह तर्क *लचमेश्वर प्रसाद शुकुल* बनाम *संघीय न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आग्रह किया गया था। केश्वर लाल चौधरी* (9), और *गुम्मलापुरा तग्गीना मोटाडा कोट्टूरुस्वामी* वी। *सेत्र वीरव्वा।* (10) इस तर्क को इस टिप्पणी के साथ पूरा किया गया था कि "उपरोक्त दो निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि वहां के तथ्य पूरी तरह से अलग और अलग-अलग थे और उनके और वर्तमान मामले के बीच कोई समानता नहीं है। कोई विधायी परिवर्तन नहीं किया गया है और यद्यपि पूर्ण पीठ द्वारा घोषित कानून इन मामलों में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून से काफी अलग है, लेकिन जो कारण बताए गए हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है, विशेष रूप से नियम या आरईएस के सिद्धांत की प्रयोज्यता के कारण।

पूर्ण पीठ द्वारा घोषित कानून को अपील के पहले समूह पर लागू करने का न्याय। इसलिए उस मामले में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क प्रबल नहीं हुआ। एक अन्य तर्क जिसका आग्रह किया गया था, वह यह था कि *सत्यध्यान घोषाल के मामले* में उनके लॉर्डशिप के फैसले के मद्देनजर केवल कानून के सवाल पर डिवीजन बेंच का निर्णय एक मध्यस्थ चरण में था और इसलिए, *न्यायिक* ता का नियम लागू नहीं होता है। इस तर्क पर जो देखा गया वह यह था- "मुझे ऐसा लगता है कि रिमांड की उपमा वर्तमान मामले में अच्छी नहीं हो सकती है। पूरी अपील को खंडपीठ को भेज दिया गया था और पीठ ने जो भी बिंदु तय किए थे, वे निर्णायक थे। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय के लिए केवल कुछ बिंदु शेष थे, जिन्हें उन्हें वापस भेज दिया गया था, लेकिन यह नियम 17 की शर्तों पर पीठ के निर्णय की निर्णायकता को कम नहीं कर सका। इसके अलावा, *सत्यध्यान घोषाल के मामले* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर, नियम 17 की वैधता के संबंध में डिवीजन बेंच का पिछला आदेश हमारे सामने चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा, चाहे हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में स्थिति जो भी हो। इसलिए यह तर्क भी विफल हो गया। इस मामले में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तब ए. *सी. एस्टेट्स बनाम ए.* एस. का उल्लेख किया है। *सेराजुद्दीन* एंड कंपनी (11), और *उत्तर रेलवे सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का प्रबंधन, जोल्हापुर* वी। *औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर* (12), लेकिन उन मामलों में तथ्य कुछ अलग थे और इसलिए, उसी के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि जहां तक वर्तमान विवाद का संबंध है, तथ्यों पर मामलों का कोई संबंध नहीं है। *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल में हेमंत कुमार भट्टाचार्जी* (13) ने पेज नंबर 1066 पर कहा, "यह तर्क एक बुनियादी गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना दिए गए गलत निर्णय की तुलना करना चाहता है। क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा एक गलत निर्णय पार्टियों के बीच उतना ही बाध्यकारी है जितना कि एक अधिकार, और केवल उच्च न्यायाधिकरणों में अपील या समीक्षा जैसी अन्य प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो कानून प्रदान करता है। 4 अप्रैल, 1952 को निर्णय देने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के पास मामले का निर्णय करने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था और तथ्य यह है कि उनका निर्णय इस न्यायालय के बाद के निर्णय से देखे गए गुण-दोष के आधार पर गलत था, यह न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के बीच कम अंतिम और बाध्यकारी नहीं बनाता है। वहां है

(5) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 935.
(6) ए.आई.आर. 1967 एस.सी.1182.
(7) ए.आई.आर. 1966 एस.सी.1061.

इस प्रकार, इस विवाद में कोई आधार नहीं है। उच्च न्यायालय का 4 अप्रैल का निर्णय; 1952; पक्षों को बाध्य करना और इसका कानूनी प्रभाव वही रहा, चाहे निर्णय के कारण ठोस हों या नहीं। उनके लॉर्डशिप का यह अवलोकन वर्तमान मामले पर बिल्कुल लागू होता है। भले ही बाद में पूर्ण पीठ की राय डिवीजन बेंच की राय से अलग हो, इसका मतलब यह नहीं है कि डिवीजन बेंच इंटर पार्टियों का निर्णय अब उन पक्षों के बीच बाध्यकारी और निर्णायक नहीं है। शब्दकोशों के विभिन्न लेखकों द्वारा दुनिया को 'मध्यस्थ' अर्थ और परिभाषा देने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर विलियम होल्ड्सवर्थ के अंग्रेजी कानून के इतिहास से ली गई बाउवियर लॉ डिक्शनरी, 1914 संस्करण में यह परिभाषा शायद अधिक उपयुक्त और बेहतर है - 'कुछ ऐसा जो किसी मुकदमे या कार्रवाई के शुरू होने और समाप्त होने के बीच किया जाता है जो कुछ बिंदु या मामले को तय करता है, जो, हालांकि, मुद्दे में मामले का अंतिम निर्णय नहीं है; जैसे, मध्यस्थ निर्णय, या फरमान, या आदेश। ऐसा लगता है कि इस शब्द की उत्पत्ति लॉर्ड एलस्मेरे के साथ हुई है; 1 होल्ड्स। ई.एल. 213." इस प्रश्न पर खंडपीठ का निर्णय कि क्या संशोधित नियम 30 इतना पूर्वव्यापी था कि इसके संशोधन की तारीख पर लंबित पुनरीक्षण आवेदनों पर लागू होता है या नहीं, एक निर्णय था, जो अपीलकर्ता की याचिका में एक बिंदु पर था, और जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, अंतिम और निर्णायक अंतर पक्ष था। इसलिए, यह एक मध्यस्थ निर्णय या आदेश नहीं था।

(8) थेरेशिया केवल एक अन्य मामले पर विचार करने के लिए एक अन्य व्यक्ति है जो मैंने ऊपर कहा है, और मामला *कांता देवी बनाम कांता देवी* का है। *कलावती* (14)। यह अब्दुर रहमान और महाजन, जेजे द्वारा दिया गया निर्णय था, निर्णय अब्दुर रहमान, जे द्वारा दिया गया था, जिसके साथ महाजन, जे, सहमत थे। मामले में वादी कांता

देवी ने एक याचिका दायर कर यह घोषणा की कि अल्पमत के दौरान कुछ मुकदमों में समझौता किया गया था, जिनमें से एक में वह पक्षकार थीं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं, उनके पति द्वारा, उनके अगले दोस्त के रूप में, उनके लिए बाध्यकारी नहीं थे क्योंकि उनके पति ने एक मुकदमे में समझौता करने और सूचीबद्ध ऋणों से बंधे होने के लिए सहमत होने में घोर लापरवाही और लापरवाही के साथ काम किया था। दूसरे सूट में। यह वह मामला था जिसे एक बड़ी पीठ को भेजा गया था और पिछली खंडपीठ द्वारा दिया गया उत्तर यह था कि अभिभावक की लापरवाही अपने आप में सहमति डिक्री को रद्द करने का आधार नहीं थी।

(8) ए.आई.आर. 1946 लाह। 419.

एक नाबालिग के खिलाफ, जिसे केवल धोखाधड़ी के आधार पर खारिज किया जा सकता है, वास्तविक या रचनात्मक। विद्वान न्यायाधीशों ने तब मामले को उस न्यायाधीश द्वारा विचारण किए जाने के लिए लौटा दिया जो इसकी सुनवाई कर रहा था। अंततः जब मामला ट्रायल अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष आया, तो उन्होंने डिवीजन बेंच इंटर पार्टियों के फैसले के बाद मुकदमा खारिज कर दिया, जिसे *कांता देवी बनाम कंता देवी* के रूप में रिपोर्ट किया गया था। *कलावती।* (15) कांता देवी वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश के फरमान के खिलाफ अपील दायर की, जो विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इस बीच यह प्रश्न *इफ्तखार हुसैन खान* बनाम *भारत मामले में पूर्ण पीठ के समक्ष था।बेअंत सिंह।* (16), जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से उत्तर लौटाया था कि किसी व्यक्ति को उसके अल्पमत के दौरान उसके खिलाफ पारित डिक्री से छुटकारा पाने में सक्षम बनाने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाना या साबित करना आवश्यक नहीं था और उसके अगले दोस्त या अभिभावक की घोर लापरवाही अकेले, यदि स्थापित हो जाती है, तो उसे उस लापरवाही के परिणामस्वरूप पारित होने पर डिक्री से बचने का अधिकार होगा। कांता देवी वादी द्वारा उच्च न्यायालय में की गई पहली अपील में, इस मामले पर भरोसा किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष का जवाब यह था कि यह मामला *पहले* डिवीजन बेंच के फैसले से अंतर-पक्षकारों के रूप में समाप्त हो गया था, जिसे कांता *देवी* बनाम *केरल के रूप में रिपोर्ट किया गया था।कलावती* (15)। अब्दुर रहमान, जे. सबसे पहले यह कहते हैं, "जब यह अपील कल हमारे सामने आई, तो मेरा विचार था कि यद्यपि कांता देवी बनाम केरल मामले में खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय *सही है* । *कलावती* (15) सही नहीं थी, फिर भी यह इस मुकदमे के पक्षकारों के लिए *दंड* के सिद्धांतों - धारा 11, सिविल प्रक्रिया संहिता - संपूर्ण नहीं होने के कारण बाध्यकारी होगा क्योंकि इस मुकदमे में इस अदालत द्वारा प्रश्न को सुना गया था और अंत में निर्णय लिया गया था और यह तथ्य कि निर्णय कानून में गलत था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि डिवीजन बेंच द्वारा जो निर्णय लिया गया था वह विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न था जो एक पूर्ण पीठ का क्षेत्र है और इस कारण से डिवीजन बेंच के निर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब विद्वान न्यायाधीश ने अपने स्वयं के इस दृष्टिकोण पर संदेह किया और देखा कि भले ही वह इस संबंध में सही नहीं था, फिर भी उसने महसूस किया कि अन्यथा भी डिवीजन बेंच का पिछला निर्णय न्यायके रूप में काम नहीं करता था /इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया पहला कारण उनके अपने शब्दों में था, "यदि मैं यह मानता हूं कि हमें इस मामले पर निर्णय लेने से न्यायिक सिद्धांतों द्वारा रोका गया था, तो यह निर्णय के कारण नहीं होगा।

(9) ए.आई.आर. 1942 205.
(10) ए.आई.आर. 1946 लाह। 235.

कांता देवी *बनाम* खंडपीठ मामले में खंडपीठ *।कलावती* (15), लेकिन अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले के कारण, हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मामले पर निर्णय लेने में उन्होंने डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त की गई राय को लागू किया था। लेकिन क्या उनके फैसले पर हमला नहीं होता अगर उन्होंने विभिन्न पक्षों के बीच एक मामले में दिए गए किसी अन्य खंडपीठ के फैसले को पूरी तरह से लागू किया होता, अगर हमने पाया कि उस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून गलत था और बाद में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया था? विद्वान न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष अपील स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से अपील थी, और विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष जो निर्णायक था वह अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय नहीं था, बल्कि उच्च न्यायालय का निर्णय था, जो अंतर-पक्षकार था और इस प्रकार न केवल मुकदमे की सुनवाई करने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश के लिए बल्कि अपील की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के लिए भी निर्णायक था। दूसरा दृष्टिकोण यह नहीं माना जा सकता है कि निर्णय वही है जब यह किसी अन्य मामले में है और यहां तक कि अंतर-पक्षकार भी नहीं है। यह तय है कि एक निर्णय अंतर-पक्षकार निर्णायक होता है और इस तथ्य के बावजूद पार्टियों को बांधता है कि किसी अन्य मामले में निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा हो सकता है, कानून के समान दृष्टिकोण नहीं ले सकता है जैसा कि एक निर्णय अंतर-पक्षकारों के बीच होता है। ताकि विद्वान न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण को संभवतः किसी भी विचार पर समर्थित नहीं किया जा सके। विद्वान न्यायाधीश ने तब सोचा कि डिवीजन बेंच का पिछला निर्णय अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से अपील में उस पीठ के समक्ष सवाल उठाने के लिए खुला था क्योंकि यह 'कानून के अमूर्त प्रश्न पर' निर्णय था, और विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि यदि पिछली डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया था, तब पहली अपील की सुनवाई करने वाली पीठ के लिए उस फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाना संभव नहीं होता। यदि मैं बड़े सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो कानून के प्रश्न पर एक निर्णय में अंतर पक्ष भी समान रूप से *शामिल* हैं, जैसा कि तथ्य के प्रश्न पर है, और विद्वान न्यायाधीश के इस तर्क को संभवतः ठोस नहीं माना जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि उन्होंने कहा, "मुझे स्पष्ट कारणों से स्वीकार करना चाहिए कि एक खंडपीठ के लिए किसी अन्य खंडपीठ की राय से असहमति जताना अनुचित है। और फिर से विद्वान न्यायाधीश ने कहा, "सभी घटनाओं में, कांता देवी बनाम *कांता देवी मामले में खंडपीठ ने फैसला* सुनाया। *कलावती* (15) अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम थी, इसे मामले के तथ्यों से जोड़ते हुए, यह वह निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय है जिसने उस कानून को लागू किया है।

इस विशेष मामले के तथ्य जो किसी अदालत को उस प्रश्न पर फिर से सुनवाई करने से रोक सकते हैं जिसे सुना गया था और अंत में फैसला किया गया था और चूंकि कानून को लागू करने वाला निर्णय वर्तमान में अपील के अधीन है, इसलिए इसे न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता है। यह पहले की तरह ही तर्क को दोहराने का एक और तरीका है। विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष अपील अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से थी, लेकिन कानून का प्रश्न, जो उसी मुकदमे में पहले डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया गया था, अंतर-पक्षकार होने के नाते, कानून के सवाल पर निर्णायक था, और जहां तक डिवीजन बेंच के उस निर्णय का संबंध था, न्याय का नियम संचालित था, न कि अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय। यह वह सब है जो कांता *देवी बनाम कांता के* मामले में कहा गया था । *कलावती* (15) और विद्वान न्यायाधीशों के संबंध में, मैं उस मामले में दृष्टिकोण से ही असहमत हूं, और अब सत्यध्यान घोषाल के मामले में उनके लॉर्डशिप के फैसले से यह दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक है/

नतीजतन, इस पीठ के समक्ष प्रश्न के पहले भाग पर मेरा उत्तर यह है कि 19 फरवरी, 1964 को खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ता की याचिका संख्या 1492 में उनके और गोधा राम प्रतिवादी 3 के बीच दिया गया निर्णय, संशोधित नियम 30 के आवेदन के प्रश्न पर होने के बावजूद एक निर्णय अंतर-पक्षकार था। पार्टियों के बीच निर्णायक और बाध्यकारी है। यह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षों के बीच निर्णायक और बाध्यकारी था और यह विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष है, और इसके विपरीत बाद में पूर्ण पीठ के फैसले के बावजूद ऐसा है। जो निर्णय अब केवल जीवन दास बनाम जीवन दास के मामले तक ही सीमित होना चाहिए । *भारत संघ, एल.पी.ए., सं.* 1966 का 1। तो जैसा कि कहा गया है, 19 फरवरी, 1964 को अपीलकर्ता की याचिका में निर्णय या डिवीजन बेंच, अन्य पक्ष, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपीलकर्ता की अपील की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी है। इस दृष्टिकोण पर, मेरी राय में, शेष आधा प्रश्न नहीं उठता है।

(9) पैनपंडित, जे.—मेरे स्वामी मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्णय को जारी करने के लिए मेरे पास 7 लाभ थे, लेकिन उनके प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं खुद को इससे सहमत होने के लिए राजी नहीं कर पाया। इसलिए, मैं एक अलग पत्र लिख रहा हूं।

इस मामले के तथ्य मेरे द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1967 के संदर्भ ति आदेश में दिए गए थे और वहां से लिए गए थे, वे निम्नानुसार हैं।

(10) इस मामले में विवाद जिला कमल के पानीपत में वार्ड नंबर 7 में संपत्ति संख्या 765 से 769 के हस्तांतरण से संबंधित है। इस संपत्ति का कुछ हिस्सा गोधा राम और चानन दास को आवंटित किया गया था, जो दोनों विस्थापित व्यक्ति थे और उनके पास क्रमशः 5,749 रुपये और 4,279 रुपये के सत्यापित दावे थे। इस विस्थापित संपत्ति का मूल्यांकन मूल्य 4,733 रुपये था। संपत्ति संख्या। आर 765 को पहली बार क्षेत्रीय निपटान आयुक्त द्वारा गोधा राम को हस्तांतरित किया गया था। उस निर्णय के खिलाफ, चानन दास ने सहायक निपटान आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की और प्रस्तुत किया कि उक्त हस्तांतरण अनुचित था क्योंकि संख्या आर - 765 से 769 सहित पूरी संपत्ति एक एकल इकाई थी और वह विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 30 के तहत इसके हस्तांतरण के हकदार थे । क्योंकि सकल मुआवजा गोधा राम की तुलना में संपत्ति के मूल्यांकन मूल्य के करीब था। 12 जनवरी, 1961 के अपने आदेश से, सहायक निपटान आयुक्त ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि पूरी संपत्ति चानन दास को हस्तांतरित कर दी जाए। इसके खिलाफ, गोधा राम ने विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 24 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और इसे 1 जून, 1961 को श्री सीपी सपरा, निपटान आयुक्त द्वारा मुख्य निपटान आयुक्त की प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ निपटाया गया। इस बीच, 24 मार्च, 1961 को नियम 30 में संशोधन किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि रहने वाले को संपत्ति हस्तांतरित करने के बजाय, जिसका सकल मुआवजा संपत्ति के मूल्य के करीब था, इसे उस निवासी को पेश किया जाना चाहिए जिसका सकल मुआवजा उच्चतम था। गोधा राम ने तर्क दिया कि संशोधित नियम 30 उनके मामले पर लागू होना चाहिए और पूरी संपत्ति उन्हें हस्तांतरित की जानी चाहिए, उनका मुआवजा चानन दास की तुलना में अधिक है। श्री सपरा का विचार था कि संशोधित नियम 30 अधिनियम की धारा 24 के तहत लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर लागू होगा। नतीजतन, उन्होंने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि पूरी संपत्ति

गोधा राम को हस्तांतरित कर दी जाए। इस आदेश के खिलाफ चानन दास द्वारा दायर अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन को केंद्र सरकार द्वारा 27 सितंबर, 1961 को खारिज कर दिया गया था। इसके कारण चनन दास द्वारा इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका (1961 का सीडब्ल्यू 1492) दायर की गई। यह रिट याचिका 31 अक्तूबर, 1963 को खन्ना, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आई और उन्होंने पाया कि रिट याचिका में शामिल बिंदु वही है जो 1961 के सीडब्ल्यू 1586 में शामिल था, जिसे गुरदेव सिंह, जे द्वारा एक खंडपीठ को भेजा गया था। इसलिए, उन्होंने निर्देश दिया कि

रिट याचिका को 1961 के सीडब्ल्यू 1586, 1963 के एलपीए 92 (मेला राम *बनाम* भारत सरकार, पुनर्वास मंत्रालय) और कुछ अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस याचिका पर तब दुआ और खन्ना, जेजे ने सुनवाई की थी। 19 फरवरी, 1964 को उन्होंने कानून के प्रश्न पर निर्णय लिया जो उन सभी मामलों में शामिल था और यह माना कि नियम 30 अपने संचालन में आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी था और यह न केवल अधिनियम के तहत अपीलों पर बल्कि धारा 24 के तहत मुख्य निपटान आयुक्त के समक्ष संशोधन और अधिनियम की धारा 33 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकांश मामलों में, वकील इस बात से सहमत नहीं थे कि कानून के बिंदु पर यह निर्णय विवाद का निर्णायक होगा और कुछ याचिकाकर्ता अन्य बिंदुओं को उठाना चाहते थे और इसलिए, यह निर्देश देना उचित होगा कि सभी रिट याचिकाओं को एकल पीठों द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 24 मार्च, 1964 को एच. आर. खन्ना, जे. के समक्ष चानन दास की रिट याचिका रखी गई और उन्होंने मेला राम मामले में खंडपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया । *भारत सरकार, पुनर्वास मंत्रालय और अन्य* (1)। इस फैसले के खिलाफ चानन दास ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की थी। अपीलकर्ता द्वारा लिया गया एक आधार यह था कि 1963 के एलपीए 92 (मेला राम के मामले) में पीठ के फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता थी। यह अपील 21 जुलाई, 1966 को मेहर सिंह, सीजे और महाजन, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आई। विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि इस न्यायालय की दो खंडपीठ के निर्णयों के बीच इस बिंदु के बारे में सीधा टकराव था कि क्या 24 मार्च, 1961 को संशोधित नियम 30 लागू होता है; अधिनियम की धारा 24 और 33 के तहत उस तारीख को लंबित या उसके बाद दायर किए गए संशोधन। इसलिए, यह निर्देश दिया गया था कि कानून के निम्नलिखित प्रश्न का निर्णय एक पूर्ण पीठ द्वारा किया जाए:

> पीठ ने कहा, "क्या 24 मार्च, 1961 को संशोधित नियम 30 उस तारीख को लंबित या उसके बाद विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 24 और 33 के तहत दायर पुनरीक्षण पर लागू होता है?

मेहर सिंह सी.जे., दुआ और महाजन, जे.जे. की पूर्ण पीठ ने कानून के इस प्रश्न की सुनवाई की। 26 सितंबर, 1966 को बहुमत के फैसले (दुआ, जे. असहमति) द्वारा, यह माना गया कि संशोधित नियम 30 इसके लागू होने की तारीख पर लंबित संशोधनों पर लागू नहीं होता है या उसके बाद धारा 24 या अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन दायर किए जाते हैं। इस फैसले के बाद

> लेटर्स पेटेंट अपील शमशेर बहादुर, जे और मेरे सामने रखी गई थी; इस मामले में दिए गए पूर्ण पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, हम लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार करने के इच्छुक थे और रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन गोधा राम के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि *कर्मचारी राज्य बीमा निगम* बनाम मैसर्स *मामले में इस न्यायालय की एक पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए। स्पैंगल्स एंड ग्लू मैन्युफैक्चरर्स और अन्य* (4), इस पूर्ण पीठ के निर्णय को तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि 19 फरवरी, 1964 को दुआ और खन्ना, जेजे द्वारा निपटाया गया कानून का प्रश्न अंतिम हो गया था और इस मुकदमे के पक्षकारों के बीच *विवाद* के रूप में कार्य करेगा और इसे पूर्ण पीठ द्वारा पुन: उत्तेजित और उलट नहीं किया जा सकता था। तथापि, कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई, क्योंकि वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, मेहर सिंह, सीजे और महाजन, जे की लेटर्स पेटेंट बेंच ने 19 फरवरी, 1964 को दुआ और खन्ना, जेजे की पिछली खंडपीठ द्वारा तय किए गए कानून बिंदु को फिर से उत्तेजित होने की अनुमति दी और चूंकि उनकी राय थी कि उस बिंदु के संबंध में इस न्यायालय की दो खंडपीठ के निर्णयों के बीच सीधा टकराव था। उन्होंने उस पीठ द्वारा तय किए गए कानून के प्रश्न को तैयार किया और इसे पूर्ण पीठ को भेज दिया। यदि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मामले में खंडपीठ द्वारा लिया गया कानून का दृष्टिकोण सही था, तो हमने महसूस किया कि मेहर सिंह, सीजे और महाजन, जे दुआ और खन्ना, जेजे द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता की जांच नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह *पार्टियों के बीच विवाद* बन गया था और आगे वे कानून के बिंदु को पूर्ण पीठ को नहीं भेज सकते थे। चूंकि ऊपर उल्लिखित दो लेटर्स पेटेंट बेंचों के बीच न्यायिक राय का टकराव था, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया था कि हम विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले में उल्लिखित कानून के प्रश्न को पूर्ण पीठ द्वारा तय किए जाने के लिए संदर्भित करें। इस प्रकार यह मामला अब हमारे सामने आया है।

(11) विद्वान गोधा राम ने तर्क दिया कि मेला राम के मामले में 19 फरवरी, 1964 को दुआ और खन्ना, जेजे द्वारा दिए गए निर्णय, जिसके साथ अपीलकर्ता प्रथम रिट याचिका (1961 का सीडब्ल्यू 1492) पर भी सुनवाई की गई थी, दोनों पक्षों के बीच *विवाद* के रूप में संचालित किया गया था और खन्ना के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट एनेल में इसकी शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। दिनांक 24 मार्च, 1964 की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

निर्णय। पहला सवाल जो तुरंत विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या गोधा राम, प्रतिवादी, को इस स्तर पर पुनर्विचार याचिका उठाने की अनुमति दी जा सकती है, जब उन्होंने उचित समय पर ऐसा नहीं किया, जब खन्ना के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता चानन दास (1964 का एलपीए 305) की लेटर्स पेटेंट अपील, जे., दिनांक 24 मार्च, 1964; अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया

21 जुलाई, 1966 को मेहरसिंह, सीजे और महाजन, जे से युक्त लेटर्स पेटेंट बेंच। यह सामान्य आधार है कि मेला राम के मामले में फैसले की शुद्धता को उस पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और अपील के एक आधार में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यह एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की मांग करता है। प्रतिवादी गोधा राम द्वारा उस समय यह दलील नहीं दी गई थी कि यह पक्षों के बीच *विवाद* के रूप में काम करता है और चानन दास को कानून के तहत इस पर सवाल उठाने से रोक दिया गया था। उस फैसले और फालशॉ, सीजे और मेहर सिंह द्वारा दिए गए फैसले के बीच संघर्ष को देखते हुए, हरबंस लाई वी में जे (जैसा कि वह तब था) *भारत संघ* (2), लेटर्स पेटेंट बेंच ने कानून के प्रश्न, जो मेला राम के मामले में तय किया गया था, को निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेज दिया। प्रतिवादी गोधा राम ने न तो लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष और न ही पूर्ण पीठ के समक्ष पूर्ण पीठ के संदर्भ पर आपत्ति जताई, जहां उनके द्वारा इस मुद्दे पर बहस की गई थी / उन्होंने कानून के उस बिंदु पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए पूर्ण पीठ को आमंत्रित किया। यह निर्विवाद है कि *न्यायिक* याचिका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में से एक नहीं है, बल्कि एक ऐसी याचिका है जिसे माफ किया जा सकता है। इसे उस पक्ष द्वारा उचित समय पर उठाया जाना चाहिए जो मुकदमेबाजी में आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए इसे स्थापित करना चाहता है; यदि कोई पक्ष *उचित स्तर पर न्याय की* मांग नहीं उठाता है , तो उसे इसे माफ करने के लिए लिया जाएगा। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा *रजनी कुमार मित्रा और अन्य बनाम अन्य मामले में आयोजित किया गया था* । *अजमदीन भुइया* (17) –

> पीठ ने कहा, "*न्यायिक कार्यवाही वह है* जो अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि बार में एक याचिका है, जिसे एक पक्ष माफ करने के लिए स्वतंत्र है।
>
> जहां दो परस्पर विरोधी आदेश हैं, अंतिम इस आधार पर लागू होना चाहिए कि कानून की नजर में यह पार्टियों के बीच बाध्यकारी है और पिछले डिक्री को बाद के मुकदमे में दलील के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए, या अब से मृत माना जाना चाहिए।

(17) ए.आई.आर. 1929 कैल. 163.

नागेरीबाला दासी वी। *श्रीदम महतो और अन्य* (18), यह देखा गया: –

> उन्होंने कहा, 'अगर कोई पक्ष अदालत में याचिका दायर नहीं करता है *तो* उसे इसे माफ करने के लिए कहा जाना चाहिए और जानबूझकर अदालत को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.'

इसी आशय का कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ का खाजे *हबीबुल्ला और अन्य* बनाम बिपिन *चंद्र राय और अन्य (19) के मामले में निर्णय है* , जहां यह टिप्पणी की गई थी: –

> "जहां वादी द्वारा अपील में, एक मुकदमे से, जिसे खारिज कर दिया गया है, हालांकि प्रतिवादियों के लिए यह खुला है कि वे न्यायिक आधार पर बर्खास्तगी के आदेश का समर्थन कर सकते हैं, *वे* ऐसा नहीं करते हैं और मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए रिमांड पर दिया जाता है, उन्हें *बाद में* पुनर्विचार याचिका उठाने से रोक दिया जाता है।

फर्म संसार *चंद लछमन दास* बनाम *दीना नाथ दुबे* (20), यह आयोजित किया गया था-

> "यदि दो अलग-अलग अदालतों में या यहां तक कि एक ही अदालत से पार्टियों द्वारा दो परस्पर विरोधी डिक्री प्राप्त की गई हैं, तो अंतिम एक पार्टियों के बीच प्रभावी डिक्री होनी चाहिए और पहली डिक्री को मृत माना जाना चाहिए। इस अभिवादन कारी नियम का आधार यह है कि यदि कोई पार्टी जो यह

चानन दास बनाम भारत संघ और अन्य (पंडित, जे।

दलील दे सकती है कि *पुन: न्याय* जब उसे अवसर दिया जाता है तो उसे यह नहीं उठाना चाहिए कि उसने इसे माफ कर दिया है। की दलील *पुन: न्याय* यह वह नहीं है जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह बार में एक याचिका है और इस तरह की याचिका को माफ किया जा सकता है।....."'

इस मामले में लागू छूट के सिद्धांत के अलावा, प्रतिवादी गोधा राम को इस स्तर पर निर्णय की याचिका उठाने से रोक दिया गया है । उन्होंने कानून के सवाल पर पूर्ण पीठ के फैसले को आमंत्रित किया और चानन दास को पहले अपनी ओर से मामले पर बहस कराने के खर्च से गुजरना पड़ा।

(18) ए.आई.आर. 1933 कैल.
(19) ए.आई.आर. 1936 कैल. 454.
(20) ए.आई.आर. 1935 645.

पूर्ण पीठ और जब पूर्ण पीठ का निर्णय अब गोधा राम के खिलाफ चला गया है, तो उन्हें यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पूर्ण पीठ उस मामले की फिर से जांच नहीं कर सकती है जो उनके और चानन दास के बीच विवाद बन गया था।

(12) इस मामले को देखने का एक और तरीका है। यदि कोई पक्ष उस समय न्यायालय में याचिका नहीं उठाता है जब इसे उठाया जाना चाहिए था, तो यह माना जाएगा कि यह प्रत्यक्ष और काफी हद तक मुद्दा है - (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के अनुसार) और उसके खिलाफ सुनवाई की गई और अंत में निर्णय लिया गया। गोधा राम ने मेहर सिंह, सीजे और महाजन की लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष इस याचिका को नहीं उठाया, जबकि उन्हें इसे उठाना चाहिए था। ऐसा होने पर यह माना जाएगा कि उस स्तर पर यह प्रत्यक्ष और काफी हद तक मुद्दा था और उसे सुना गया और अंत में उसके खिलाफ फैसला किया गया।

(13) इन सभी परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि गोधा राम को, कानून के तहत, पूर्ण पीठ के फैसले के बाद *पुनर्विचार याचिका* उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और वह बाद के फैसले से बाध्य होंगे। मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, और मैं यह बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, कि पूर्ण पीठ के निर्णय को केवल 19.66 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 1 *(जीवन दास* बनाम *भारत बनाम भारत) में प्रभावी माना जाएगा।भारत संघ)* जिस पर चानन दास की लेटर्स पेटेंट अपील के साथ भी सुनवाई की गई थी, और अपीलकर्ता के मामले को प्रभावित नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने कहा है, *न्यायिक* याचिका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि बार में एक याचिका है जिसे एक पक्ष माफ करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, *चानन दोस के मामले* में पूर्ण पीठ के फैसले को अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं माना जा सकता है।

(14) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलकर्ता ने शमशेर बहादुर, जे. और मेरे समक्ष अपना पक्ष रखा था, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता, तो संभवतः पूर्ण पीठ को इस संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन, किसी भी दर पर, इस पूर्ण पीठ को भेजे गए कानून के प्रश्न को उस मामले के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता है जिसमें यह उठा था और तर्क दिया गया था। पहले बिंदु के संबंध में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, मेरी राय में, पूर्ण पीठ के निर्णय के आधार पर अपील की स्वीकृति होगी और संदर्भ का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(15) यदि मैं ऊपर दिए गए पहले बिंदु को गलत मानता हूं, तो अगला सवाल यह है कि क्या मेला राम के मामले में दुआ और खन्ना, जेजे की पीठ का 19 फरवरी, 1964 का फैसला चनन दास और गोधा राम के बीच विवाद के रूप में काम करता है। यह संदेह से परे है कि डिवीजन बेंच ने 24 मार्च, 1961 को संशोधित विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियमों के नियम 30 के पूर्वव्यापी संचालन की सीमा के बारे में कानून के बिंदु पर फैसला किया और अपने फैसले के अनुसार एलपी को 1962 की संख्या 384 और 1963 की संख्या 92 के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने यह निर्देश देना उचित समझा कि इन परिस्थितियों में चनन दास की रिट याचिका (1961 का सीडब्ल्यू 1492) सहित निर्णय के लिए भेजे गए सभी रिट याचिकाओं को अब एकल पीठ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए। 1961 की सी.डब्ल्यू.1492 पर निर्णय लेने के लिए खन्ना ने 24 मार्च, 1964 को मेला राम के मामले में खंडपीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच ने केवल सार में कानून के बिंदु का फैसला किया और इसे केवल एल.पी. 1962 की धारा 384 और 1963 की धारा 92 के अनुसार अपीलकर्ता *सहित अन्य रिट याचिकाओं पर इसे लागू करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश पर छोड़ दिया।* इसलिए, यह स्पष्ट है कि मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को चानन दास और गोधा राम के *बीच* अंतर नहीं कहा जा सकता है जो 1961 के सीडब्ल्यू 1492 के पक्षकार थे। यह खन्ना, जे. द्वारा पारित 4 मार्च, 1964 का निर्णय था, जिसे कानून में पारस्परिक माना जा सकता *है/यह* वह था जिसने चानन दास की रिट याचिका के तथ्यों पर कानून के अमूर्त प्रस्ताव पर डिवीजन बेंच के फैसले को लागू किया था और यह उनके फैसले की शुद्धता थी जिसे चानन दास द्वारा दायर 1964 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 305 में चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उक्त बेंच द्वारा उनकी रिट याचिका पर इसे लागू नहीं किया गया था। उनका एकमात्र उपाय खन्ना, जे के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील दायर करना था और वहां

आग्रह करना था कि मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच का निर्णय जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके मामले पर लागू किया गया था, गलत था। मेला राम के मामले में फैसला *एक-दूसरे के खिलाफ नहीं होने के* कारण गर्म हो सकता है, इसलिए यह न्यायिक रूप से काम कर सकता *है*

(16) कर्मचारी राज्य बीमा निगम मामले में *मेहर सिंह, सी.जे. और ग्रोवर, जे., की पीठ के फैसले पर प्रतिवादी के पक्ष* में एक अच्छा सौदा किया गया था, जो मेला राम के मामले में उनके तर्क के समर्थन में था।

मैं

पार्टियों के बीच विवाद के रूप में संचालित होता है। सबसे पहले, उस मामले में, *पुनर्विचार* याचिका की याचिका तब ली गई जब पूर्व डिवीजन बेंच के निर्णय के अनुसार रिट याचिका पर निर्णय लेने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील सुनवाई के लिए आई। वहां, *उचित* समय पर निर्णय की याचिका ली गई थी और यह नहीं कहा जा सकता था कि इसे माफ कर दिया गया है। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरे, मेरा मत है कि न्यायपालिका से संबंधित कानून के मुद्दे *पर, मैं* विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ कहता हूं, सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर अब्दुर रहमान और एम सी महाजन, जे जे द्वारा *माउंट कांता देवी बनाम माउंट कांता देवी* मामले में निर्णय लिया गया। *श्रीमती कलावती और अन्य* (14) को विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया था, जो कि मेरी राय में, मैं फिर से सम्मान के साथ कहता हूं, इस मुद्दे पर सही कानून निर्धारित करता है। इसमें, यह आयोजित किया गया था-

> "एक खंडपीठ केवल मामले के तथ्यों से अलग कानून के एक अमूर्त प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकती है, जिसे उसे तय करने के लिए बुलाया गया है। यह एक पूर्ण पीठ का प्रांत है जब किसी बिंदु को राय के लिए भेजा जाता है। मामले के तथ्यों से अलग, कानून के शुद्ध प्रश्न पर एक खंडपीठ की राय का दूसरी खंडपीठ पर वैसा ही बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है जैसा कि पूर्ण पीठ के फैसले का होगा, हालांकि एक खंडपीठ के लिए दूसरी डिवीजन बेंच की राय से असहमति जताना अनुचित है।
>
> (17) एक खंडपीठ ने मामले पर निर्णय लिए बिना, केवल एक राय व्यक्त की कि इस विषय पर कानून क्या था, और उस राय को उस न्यायाधीश द्वारा लागू करने के लिए छोड़ दिया जो एक अधीनस्थ न्यायाधीश था। डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए, अधीनस्थ न्यायाधीश ने वाद को खारिज कर दिया। वादी ने उच्च न्यायालय में अपील की और अपील एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इस बीच, एक पूर्ण पीठ ने उसी विषय पर अपनी राय दी, जो पिछली डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त की गई राय के विपरीत थी:
>
> (18) यह माना गया कि डिवीजन बेंच के फैसले को मुकदमे के पक्षकारों के बीच विवाद नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह तथ्यों पर उसका अंतिम निर्णय नहीं था।
>
> मामला. यहां तक कि अगर डिवीजन बेंच मामले के तथ्यों पर लागू किए बिना अपनी राय व्यक्त करने के लिए सक्षम थी, तो यह वह निर्णय नहीं था, बल्कि वह निर्णय था जिसने उस कानून को मामले के तथ्यों पर लागू किया था जो अदालत को उस प्रश्न को फिर से सुनने से रोक सकता था जिसे सुना गया था और अंत में फैसला किया गया था और जैसा कि कानून को लागू करने वाला निर्णय अपील के अधीन था, इसे न्यायिक नहीं माना जाएगा /

यदि किसी खंडपीठ द्वारा कानून के किसी बिंदु का सार में निर्णय लिया जाता है, तो वह निर्णय एक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता *है जिसे न्यायिक के* रूप में पेश किया जा सकता है / यह निर्णय *एकल* न्यायाधीश का निर्णय होगा, जिन्होंने खंडपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले का फैसला किया और इस मामले में वह निर्णय खन्ना, जे. *सत्यध्यान घोषाल और अन्य* बनाम अन्य मामले *में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। श्रीमती देवराजिन देही और एक अन्य* (3), जिन पर *कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मामले* में भरोसा किया गया था, स्पष्ट रूप से अलग-अलग थे। उस मामले में, पूर्व निर्णय, जिसे *न्यायाधीन* माना गया था, उसी मामले में आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका में दिया गया था और यह किसी अमूर्त प्रस्ताव या कानून के दृष्टिकोण पर दिया गया निर्णय नहीं था, और इसके अलावा, यथाशीघ्र न्याय की मांग की गई थी। इसलिए, *सत्यध्यान घोषाल* के मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियां न तो तत्काल मामले पर और न ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मामले पर लागू होती हैं -

> "न्यायिक ता *का सिद्धांत* एक ही मुकदमे में दो चरणों के बीच इस हद तक भी लागू होता है कि एक

> अदालत, चाहे ट्रायल कोर्ट हो या उच्च अदालत, जिसने पहले चरण में एक तरह से किसी मामले का फैसला किया हो, पार्टियों को उसी कार्यवाही के बाद के चरण में मामले को फिर से उत्तेजित करने की अनुमति नहीं देगा।

(19) यदि मैं सही हूँ कि बेंची का निर्णय विनआईएम रेन का मामला चानन दास और गोधा राम के बीच विवाद के रूप में काम नहीं कर सकता है, तो लेटर्स पेटेंट बेंच, जो अंततः चानन दास की अपील पर सुनवाई कर रही थी, के समक्ष स्थिति यह थी कि चानन दास बनाम चानन दास मामले में पूर्ण पीठ *थी* । *इस बीच, भारत संघ और अन्य ने* मेला राम के मामले में फैसले को पलट दिया था। लेटर्स पेटेंट बेंच तब पूर्ण पीठ के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य थी जो

बाद में दिया गया था, और इसके अनुसार मामले का फैसला करें। मेला राम के मामले में निर्णय पक्षों के लिए अब बाध्यकारी नहीं था और इसे पूर्ण पीठ के फैसले से बदल दिया गया था, जो प्रभावी हो गया और जिसके द्वारा पार्टियां बाध्य थीं।

(20) मान लीजिए, मेलाई राम के मामले में निर्णय चानन दास और गोधा राम के लिए अपरिहार्य और बाध्यकारी था, तो क्या स्थिति होगी यदि इस बीच कानून में वैधानिक परिवर्तन होता है या खन्ना के समक्ष रिट याचिका आने से पहले डिवीजन बेंच द्वारा तय किए गए कानून के सवाल पर विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। 24 मार्च, 1964 को? चानन दास की रिट याचिका पर निर्णय लेते समय खन्ना, जे. द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया होगा? जाहिर है, मेरे विचार में, विद्वान न्यायाधीश को वैधानिक कानून में बदलाव का नोटिस लेना चाहिए था या डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए था, क्योंकि रिट याचिका अभी भी लंबित थी और अंतिम रूप से फैसला नहीं किया गया था। यदि ऐसा नहीं होता, तो परिणाम यह होता कि विद्वान एकल न्यायाधीश स्पष्ट रूप से एक गलत निर्णय का पालन कर रहे होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी नहीं कर रहे होंगे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह जो निर्णय दे रहे थे वह कानून के अनुसार नहीं था। पीड़ित पक्ष उक्त निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील दायर करने के लिए मजबूर होगा और वहां भी उसे इस दलील के साथ मुलाकात की जाएगी कि कानून का सवाल पार्टियों के बीच विवाद बन गया है और लेटर्स पेटेंट बेंच भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं करेगी, हालांकि इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था और अपील में रद्द किया जाना था। उक्त न्यायालय द्वारा। इन सबका नतीजा यह होगा कि पार्टी न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएगी और दोनों चरणों में हाईकोर्ट पार्टी को राहत देने में पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा होगा, हर समय यह जानते हुए कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर अधिकार के रूप में इसका हकदार है। इस प्रकार, पीड़ित पक्ष को बिना किसी कारण के यह सब खर्च और परेशानी उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस तरह की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और मैं इस विचार से सहमत होने में असमर्थ हूं जो इस तरह के परिणाम का कारण बन सकता है। यह शायद इस तरह के मामलों के कारण था जो इस तरह के विसंगतिपूर्ण परिणामों का कारण बनता था कि संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने *लछमेश्वर प्रसाद श्वकुल और अन्य* मामले *में फैसला सुनाया था।केश्वर लाई चौदरी और अन्य। (9))* और *गुम्मलापुटाज़ कोट्टुस्वामी* वी. *सेत्रा वीरव्वा और अन्य* (10) ने क्रमशः माना कि किसी पार्टी को दी जाने वाली राहत को ढालते समय कानून और परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता होने के कारण, अपील की सुनवाई करने वाले बेइच को, मेरी राय में, कानून में वैधानिक परिवर्तन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित या न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार निर्णय लेना होगा जिसमें उक्त अपील लंबित थी। *लचमेश्वर प्रसाद शुकुल के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा यह देखा गया था-*

> "भारत के प्रक्रियात्मक कानून के तहत अपील की सुनवाई पुन: सुनवाई की प्रकृति में है और इसलिए, अपील पर एक मामले में दी जाने वाली राहत को ढालने में, अपीलीय न्यायालय उन तथ्यों और

घटनाओं को भी ध्यान में रखने का हकदार है जो डिक्री के खिलाफ अपील के बाद अस्तित्व में आए हैं। शक्तियां केवल यह देखने तक सीमित नहीं हैं कि क्या निचली अदालत का फैसला कानून के अनुसार सही था क्योंकि यह उस समय खड़ा था जब उसका फैसला दिया गया था।

इसी तरह, गुम्मलापुरा तागिना माताडा कोट्टुरुस्वामी के मामले *में सुप्रीम कोर्ट* ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय था कि अपीलीय अदालत कानून में किसी भी बदलाव पर विचार करने की हकदार थी। इन परिस्थितियों में, चूंकि लेटर्स पेटेंट अपील अभी भी लंबित थी, इसलिए पूर्ण पीठ के निर्णय से कानून में जो परिवर्तन हुआ है, मेरी राय में, उसे प्रभावी किया जाना चाहिए और राहत को उसके अनुरूप ढाला जाना चाहिए।

(21) अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जहां तक अपीलकर्ता की रिट याचिका (1961 का सीडब्ल्यू 1492) का संबंध है, मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच का निर्णय एक मध्यस्थ प्रकृति का था, क्योंकि इसने केवल उसमें उत्पन्न होने वाले कानून के एक बिंदु का फैसला किया था और जो अंततः पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित नहीं करता था। यह आदेश, एक वार्ताकारी प्रकृति का होने के नाते, खन्ना, जे. द्वारा रिट याचिका के अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील में उत्तेजित किया जा सकता है। इस विवाद में भी कुछ दम नजर आता है। व्हार्टन का लॉ लेक्सिकन एक वार्ताकारी आदेश या निर्णय का वर्णन करता है जो किसी कार्रवाई की प्रगति के दौरान किया गया या दिया गया था, लेकिन जो अंत में 'का निपटान नहीं करता है'

> पार्टियों के अधिकार। अय्यर के लॉ लेक्सिकन के अनुसार, एक मध्यस्थ आदेश वह है जो सुनवाई से पहले कारण लंबित होने तक दिया जाता है। खूबियां। प्रगति के लिए आवश्यक और आवश्यक कुछ अंत और उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए एक मध्यस्थ आदेश बनाया जाता है।
>
> सूट का। मेला राम के मामले में फैसले ने केवल विभिन्न याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले कानून के एक बिंदु का फैसला किया, लेकिन इसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उसमें उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय के साथ प्रत्येक रिट याचिका पर लागू करने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार, यह रिट याचिका की प्रगति के दौरान दिया गया निर्णय था, जिसे अंततः खन्ना, जे. द्वारा निपटाया गया था। यह निर्णय एक मध्यस्थ मामले पर होने के कारण, 24 मार्च, 1964 को खन्ना, जे द्वारा दी गई रिट याचिका के अंतिम निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि मेला राम के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अपीलकर्ता को इस दलील के साथ पूरा किया गया होगा कि उसकी रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। जैसा कि *सत्यध्यान घोषाल के मामले* में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह स्पष्ट था कि एक मध्यस्थ आदेश, जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी क्योंकि कोई अपील नहीं थी या भले ही अपील नहीं की गई थी, अपील नहीं ली गई थी, उसे अंतिम डिक्री या आदेश से अपील में चुनौती दी जा सकती थी। इसलिए, इस आधार पर भी, मेला राम के मामले में फैसले को लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

(22) मैं *अपने निर्णय के एक भाग में कहा है, चूंकि इस स्तर पर गोधा राम के समक्ष न्यायिक याचिका* उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मेरी राय में, इस संदर्भ की आवश्यकता इस मामले में उत्पन्न नहीं होती। यदि, हालांकि, यह माना जाता है कि *प्रतिवादी* के लिए निर्णय की याचिका उपलब्ध थी, तो, ऊपर बताए गए कारणों के लिए, संदर्भित प्रश्न का मेरा उत्तर निम्नानुसार होगा। तथापि, एक मामला है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पूर्ण पीठ को भेजे गए कानून के प्रश्न में यह माना गया है कि जिस खंडपीठ को मामला भेजा गया था, उसने कानून के अमूर्त प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद इसे उस मामले के तथ्यों पर लागू किया था और उसमें *उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं* पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिया था , ताकि डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया कानून का बिंदु अंतिम और बाध्यकारी हो जाए / ऐसी आकस्मिकता में, डिवीजन बेंच का निर्णय, निश्चित रूप से, बाद के चरण में न्यायिक *हस्तक्षेप* के रूप में काम करेगा।

और विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर मामले का फैसला किया जाएगा, बशर्ते कि उचित स्तर पर लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय लिया गया हो। हालांकि, वर्तमान, मेरी राय में, उस तरह का मामला नहीं है। यदि, हालांकि, अपने द्वारा तय किए गए कानून के बिंदु को लागू किए बिना, डिवीजन बेंच मामले को अंतिम निर्णय के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज देती है, तो डिवीजन बेंच का आदेश न्यायिक रूप से काम नहीं करेगा, *न कि* अंतिम रूप से परस्पर निर्णय लिया गया *है।* उस मामले में, निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश का होगा और उनके फैसले से लेटर्स पेटेंट अपील में, अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह पहले की डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता को चुनौती दे सकता है। लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई करने वाली पीठ के लिए उचित तरीका यह होगा कि कानून के प्रश्न को निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेजा जाए, यदि उसे पिछली खंडपीठ के निर्णय की शुद्धता पर संदेह है। यदि, इस बीच, एक पूर्ण पीठ ने पहले ही कानून के उस बिंदु को अलग तरीके से तय किया था, तो लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई करने वाली पीठ उस निर्णय का पालन करेगी और उसे प्रभावी बनाएगी, न कि पिछली डिवीजन बेंच के। भले ही डिवीजन बेंच द्वारा तय किए गए कानून के प्रश्न को उक्त पीठ द्वारा उस मामले के तथ्यों पर लागू किया गया था और कानून के बिंदु को *पारस्परिक रूप से सुलझा लिया गया था* और न्यायिक बन गया था, लेकिन यदि इस बीच, लेटर्स पेटेंट अपील के लंबित होने के दौरान, कानून में वैधानिक परिवर्तन हुआ था या सुप्रीम कोर्ट या उसी की पूर्ण पीठ का निर्णय हुआ था। उच्च न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा था कि पत्र पेटेंट पीठ अपीलकर्ता को दी जाने वाली राहत को ढालते हुए इसे लागू करेगी।

(23) *ननरूला,* जे.—मुझे अपने प्रभु, मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित न्याय और मेरे विद्वान भाई श्री पंडित जे के नोट के माध्यम से इस बात का लाभ मिला है। मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं:-

(1) 19 फरवरी, 1964 को उस रिट याचिका पर एक निर्णय दिया, जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, मेला राम के मामले के निपटारे के समय कि संशोधित नियम 30 विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (1954 का 44) की धारा 24 के तहत आवेदनों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। जो थे

नियम 30 के संशोधन के समय मुख्य निपटान आयुक्त के समक्ष लंबित;

(2) 19 फरवरी, 1964 के डिवीजन बेंच के उक्त फैसले को आमतौर पर "वार्ताकारी आदेश" के रुप में जाना जाता है;

(3) यह कि नियम 30 के संशोधन के पूर्वव्यापी संशोधन से संबंधित इस मुद्दे पर खंडपीठ का निर्णय न केवल खन्ना, जे के समक्ष मूल चरण में रिट याचिकाकर्ता अपीलकर्ता के खिलाफ सुनवाई के रुप में न्यायाधिकार के रुप में संचालित हुआ , बल्कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाली एक अन्य पीठ के समक्ष उस प्रश्न को फिर से खोलने पर भी रोक लगाता है। वही; मूल चरण में पहले डिवीजन बेंच या अभी भी बड़ी बेंच के संदर्भ में उसी परिणाम को प्राप्त करके; और नतीजतन।

(24) <(iv) 1 कि यदि कोई विद्वान एकल न्यायाधीश किसी मामले को खंडपीठ के पास भेजता है और उक्त खंडपीठ केवल कानून के प्रश्न का निर्णय करती है और फिर मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेज देती है, तो लेटर्स पेटेंट बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील में पिछली डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच नहीं कर सकती है। कानून का उपरोक्त प्रश्न।

मैं अपने प्रभु, मुख्य न्यायाधीश से भी सहमत हूं कि प्रश्न के पहले भाग के पूर्वोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार संदर्भित शेष प्रश्न नहीं उठता।

(25) मेरे विद्वान भाई पंडित जे. जे. द्वारा प्रस्तावित निर्णय में इस आशय का अतिरिक्त प्रश्न उठाया गया है कि क्या प्रतिवादी को इस स्तर पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है, जब उसने ऐसा नहीं किया है "उचित समय पर जब अपीलकर्ता चानन दा की लेटर्स पेटेंट अपील (यह अपील) लेटर्स पेटेंट के समक्ष सुनवाई के लिए आई है। 21 जुलाई, 1966 को मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश और महाजन, जे की पीठ ने मेरा विचार व्यक्त किया: –

(1) यह याचिका हमारे समक्ष पहली बार नहीं उठाई गई है , बल्कि खंडपीठ के समक्ष उठाई गई है।

शमशेर बहादुर और पंडित, जेजे और दूसरे पक्ष ने उस समय गोधा राम प्रतिवादी की याचिका को लागू नहीं किया था, जिसने उस आपत्ति को उठाने का अधिकार माफ कर दिया था, मेरे विद्वान भाई से अपील की गई दलील की समानता पर यह तर्क देना संभव है कि याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से न्याय की आपत्ति के खिलाफ माफी की याचिका उठाने का अधिकार माफ कर दिया *है;*

(2) यदि मेरे भगवान पंडित, जे से अपील की गई संभावित आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा उस खंडपीठ के समक्ष उठाई गई थी, जिसके मेरे विद्वान भाई सदस्य थे, और यदि छूट की याचिका उक्त लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष प्रबल होती, तो उस पीठ द्वारा इस विशेष संदर्भ का कोई सवाल ही नहीं उठता:

(3) लेटर्स पेटेंट अपील को इस पूर्ण पीठ को नहीं भेजा गया है, लेकिन एक विशिष्ट प्रश्न को उत्तर देने के लिए भेजा गया है। मेरी राय में उस प्रश्न का कोई भी हिस्सा ऊपर उल्लिखित छूट की दलील पर हमारे मनोरंजक या निर्णय लेने की संभावना को स्वीकार नहीं करता है। इस पूर्ण पीठ को भेजे गए प्रश्न का उत्तर हम जिस भी तरह से दें, लेटर्स पेटेंट अपील को कानून के अनुरूप निपटान के लिए खंडपीठ के पास वापस जाना होगा। यदि उस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष छूट की आपत्ति उठाई जाती है और प्रतिवादी सफलतापूर्वक आग्रह करने में सक्षम नहीं होता है कि याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ से पहले इसे न उठाकर इस आपत्ति को उठाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस पीठ के लिए खुला होगा जिसके समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है। पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों को फिट और उचित होना चाहिए; और

(4) किसी भी स्थिति में, मैं अपने विद्वान भाई द्वारा प्रस्तावित आदेश में उल्लिखित छूट की संभावित याचिका पर किसी न किसी तरह से फैसला करने के लिए खुद को तैयार नहीं मानता क्योंकि संदर्भ की सुनवाई में किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया और इस पर हमारे संभावित निर्णय से प्रभावित पक्ष को सुने बिना उक्त ओलिया को अनुमति देना लेटर्स पेटेंट पर लगभग फैसला करने के समान होगा।

1.00

चानन दास बनाम भारत संघ और अन्य (नरूला, जे।

प्रतिवादी के खिलाफ अपील (जैसा कि पहले ही कहा गया है, हमें संदर्भित नहीं किया गया है) उस बिंदु पर जिस पर उसे हमें संबोधित करने का कोई अवसर नहीं मिला था।

इसलिए, मेरी राय है कि इस पूर्ण पीठ में बैठे हुए हमारे लिए यह तय करने का विकल्प खुला नहीं है कि क्या *न्यायिक* याचिका उचित स्तर पर उठाई गई थी या नहीं, और क्या प्रतिवादी ने उक्त याचिका को माफ कर दिया था या अन्यथा उसे उठाने से रोक दिया गया था। ये ऐसे मामले हैं जिनके साथ हमें संदर्भित प्रश्न के हमारे उत्तर के अनुसरण में अपील की सुनवाई करने वाली पीठ को विचार करना होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मुझे इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं लगता कि जिस खंडपीठ ने मेला राम के मामले का फैसला किया और जिस रिट याचिका से यह अपील उठी है, उसमें नियम 30 के संशोधन की पुनरावलोकन से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया, जिसने इस मामले के तथ्यों पर पुनरावलोकन के लिए अपना निर्णय लागू किया और रिट याचिका खन्ना को भेज दी। केवल उसमें उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए, ताकि डिवीजन बेंच (दुआ और खन्ना, जेजे) द्वारा तय किया गया कानून का बिंदु अंतिम और बाध्यकारी हो जाए / मैं अपने विद्वान भाई पंडित जे से सहमत हूं कि ऐसी आकस्मिकता में, जो मेरे अनुसार वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से आकस्मिकता है, 19 फरवरी, 1964 का डिवीजन बेंच का निर्णय, न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में कार्य करेगा, और इसे विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम निर्णय से इस लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को स्पष्ट रूप से किसके पास वापस भेजा गया था, केवल उसमें उठने वाले अन्य बिंदुओं पर। इन टिप्पणियों के साथ, मैं उस उत्तर (हमें संदर्भित प्रश्न का) से सहमत हूं जो मेरे प्रभु, मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित किया गया है। मैं यह भी निर्देश दूंगा कि इस संदर्भ की लागत पार्टियों द्वारा वहन की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा वहन किया गया है। लेटर्स पेटेंट अपील की लागत का शेष हिस्सा निश्चित रूप से पीठ के विवेक ाधिकार में होगा, जो अंततः अन्य बिंदुओं पर अपील की सुनवाई और निपटान करेगा।

पूर्ण पीठ का आदेश

(26) बहुमत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न के पहले भाग का उत्तर यह है कि यदि एक विद्वान एकल न्यायाधीश किसी मामले को एक खंडपीठ को संदर्भित करता है और उक्त खंडपीठ केवल कानून के प्रश्न का निर्णय करती है और फिर मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज देती है, लेटर्स पेटेंट बेंच, फाइनल के खिलाफ अपील मेंविद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय, कानून के उपरोक्त प्रश्न पर पिछली खंडपीठ के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच नहीं कर सकता है। प्रश्न के पहले भाग के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न का शेष भाग, इस प्रकार संदर्भित, प्रश्न नहीं उठता।

पार्टियों को इस संदर्भ में अपनी लागत वहन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषामें इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा